के पहले पांच महीनों
तक पहुंच गया, जो
जर से लगभग तीन
ा आंकड़ा पहले ही
लर के निर्यात का

रिज़ॉर्ट
टन

रेचम बंगाल के
ाषणा की। गंगा
मणीय ग्रामीण
शक एवं मुख्य
ीर रिज़ॉर्ट एंड
ं विस्तार करने
कुटीर रिज़ॉर्ट
ोच-समझकर
भरपूर हैं और
यक्ष हर्षवर्धन
ो आगे बढ़ाते
वें संस्करण,
ास न केवल
बल्कि क्षेत्र
बढ़ावा देने

प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के विस्तार पर संयुक्त रूप से 25,760 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इन कंपनियों ने नई एवं मौजूदा परियोजनाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। बॉटलिंग इकाई पेय पदार्थ को बोतलों में भरकर पैक करती है और उसे बाजार में बिक्री के लिए पहुंचाने का काम करती है। बॉटलिंग इकाई) और कधारा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू सहित नौ राज्यों में किया जाएगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के 30,000 प्रत्यक्ष और 3,00,000 अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

जीएसटी विसंगति से 20 हजार कॉरगेटेड बॉक्स इकाइयों के बंद होने का खतरा

कोलकाता : देशभर में फैले कॉरगेटेड पेपर पैकेजिंग उद्योग की लगभग 20,000 इकाइयां 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। यह 100% एमएसएमई-संचालित क्षेत्र सालाना 70 लाख टन क्राफ्ट पेपर को कॉरगेटेड पैकेजिंग में बदलता है। जीएसटी 2.0 के तहत, कॉरगेटेड पेपर बोर्ड बॉक्स (कार्टन, बॉक्स) पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके कच्चे माल - क्राफ्ट पेपर और बोर्ड पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने से उलटा शुल्क ढांचा बन गया है, जिससे उद्योग पर 13% का बोझ पड़ रहा है। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट संचय के कारण पैसा फंसता है, खर्च बढ़ता है, ठेका मजदूरी, जॉब वर्क, किराया, मरम्मत और रखरखाव पर लागत बढ़ जाती है। साथ ही, आम आदमी के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। ईस्टर्न इंडिया कॉरगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल व पूर्व अध्यक्ष मिलन कुमार डे ने सरकार से मांग की है कि कागज और बोर्ड के साथ कॉरगेटेड बक्सों पर जीएसटी दरों में समानता बहाल की जाए। चूंकि इनकी सप्लाई बी2बी होती है, इसलिए सरकार के राजस्व पर भी कोई असर नहीं आएगा।

इस तरह के समर्थन से भारतभर के हजारों कन्वर्टर्स को बहुत जरूरी राहत मिलेगी और वॉकल फॉर लोकल व मेक इन इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

Sanmarg
Dated 26/09/25